Email : mazdoormorcha@yahoo.co.in

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक

नेट पर उपलब्ध :
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 R.N.I. No. 66400/97

मुकदमा दर्ज होने से बौखलाये डीएवी के डायरेक्टर 3

झुग्गी बस्तियों पर लटकी है तोड़फोड़ की तलवार 4

20–21 फरवरी की देशव्यापी हड़ताल : मज़दूर आन्दोलन में एक नई करवट 6

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मज़दूरों की दुर्दशा 7

वर्ष 26 अंक 8 फरीदाबाद, शुक्रवार, 1-15 मार्च 2013 फोन : - 9999595632 सहयोग राशि 2 रुपया

कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करेंगे : नये सीपी चावला

16 लाख की लूट व हत्या करके अपराधियों ने भी तुरन्त दिया जवाब

फ़रीदाबाद (म.मो.) नवनियुक्त पुलिस कमिश्नर अरशिन्द्र सिंह चावला ने दिनांक 22 फ़रवरी को पत्रकारों को अपने कार्यालय में बुला कर बताया कि वह कैसे कैसे, किन किन तरीकों से शहर की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को सुधार कर अपराधियों की नकेल कसेंगे। उनकी यह पत्रकार वार्ता समाप्त होने के तुरन्त बाद अपराधियों ने भी जवाबी कार्यवाही की। अपनी मौजूदगी एवं दक्षता सिद्ध करते हुए उन्होंने शहर के बीचों बीच, राष्ट्रीय राजमार्ग पर थाना सेक्टर 31 के क्षेत्र में एक व्यक्ति को गोली मारकर 17 लाख रुपये लूट लिये।

घटनास्थल के एक सिरे पर बड़खल चौक व दूसरे सिरे पर एन एच पी सी चौक हैं। इन दोंनों ही स्थानों पर दो-दो चार-चार पुलिसकर्मी सदैव 'तैनात' रहते हैं। इनके अलावा कम से कम दो पुलिस जिप्सियां भी तैनात रहती हैं। इस छोटे से क्षेत्र में जी टी रोड से सट कर एक पुलिस चौकी, थोड़ा हट कर डी एल एफ की सी आई ए चौकी, थोड़ा सा और पीछे हट कर थाना सेक्टर 31 भी कायम है। इसके बावजूद कार को रुकवा कर हत्या व लूट की वारदात को अन्जाम दे कर अपराधी फ़रार होने में कामयाब रहे पुलिस हमेंशा की तरह मौका ए वारदात पर पहुंच कर

सीपी चावला : अपराध नियंत्रित करेंगे ?

लकीर पीटती रही। बेशक यह संयोग ही हो, लेकिन अपराधियों ने अपनी दीदा दिलेरी से चावला को यह संदेश तो दे ही दिया कि उन पर काबू पाना इस अपाहिज एवं भटकी हुई पुलिस के बस का नहीं है। वे जब चाहें जहां चाहें कोई भी वारदात करके भागने में समर्थ हैं। जो लोग सुरक्षित हैं वे केवल इस लिये हैं कि वे अपराधियों के निशाने पर अभी नहीं है। उनकी सुरक्षा का श्रेय पुलिस को लेने की जरूरत नहीं। अपराध बेकाबू होने का मूल कारण जानने के लिये अपराधी व उसे पकड़ने वाले पुलिसकर्मी की मानसिकता को समझना जरूरी है।

अपराधी किसी भी वारदात को पूरी निष्ठा एकाग्रता व तन्मयता से अंजाम देता है। उसे यह मालूम होता है कि जरा सी भी चूक उसे बहुत भारी पड़ सकती है। इसलिये वह कोई भी वारदात सिर धड़ की बाज़ी लगा कर करता है। दूसरी ओर पुलिसकर्मी केवल नौकरी पीटता है।

शेष पेज 2 पर

ई एस आई सी की 61 वीं वर्षगांठ पर

विज्ञापनों में अपनी पीठ थपथपाती सरकार

फ़रीदाबाद (म.मो.) देश भर के औद्योगिक मज़दूरों को स्वास्थ्य सेवाऐं तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा गठित ई एस आई सी-कर्मचारी राज्य बीमा निगम को गत सप्ताह 61 वर्ष पूरे हो गये। इस अवसर पर भारत सरकार के श्रम मन्त्रालय ने अपने दो मन्त्रियों के चित्र वाले विज्ञापन देश भर के अखबारों में छपवा कर पूरी बेशर्मी से अपनी पीठ थपथपाई है।

विदित है कि ई एस आई निगम अपनी उक्त तथाकथित सेवाओं के बदले मज़दूरों के वेतन का साढे छह प्रतिशत वसूलती है। स्वास्थ्य सेवाएं देने के नाम पर निगम ने जगह-जगह डिस्पेंसरियां व अस्पताल तो स्थापित कर रखे हैं, परन्तु केवल दिखावे के लिये। इनके भरोसे बीमार मज़दूर शायद ही कभी ठीक हो पाता होगा। जिस ढंग से, मज़दूरों की पहुंच से दूर-दूर, तथा अपर्याप्त संख्या में इनको स्थापित किया गया है उनका वहां पहुंचना ही कठिन होता है। जैसे-तैसे यदि वहां पहुंच भी गये तो वहां न तो पर्याप्त स्टाफ़ है, न ही आवश्यक चिकित्सा उपकरण एवं दवायें। इन कठोर एवं भयानक परिस्थितियों को देखते हुए मरीज या तो नीम हकीम के हत्थे चढता है और यदि समर्थ है तो निजि अस्पतालों की शरण में जाता है। निगम के अस्पतालों के भरोसे केवल वही लोग रहते हैं जो अपनी जान जोखिम में डालने को अभिशप्त हैं।

> **सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाले ऐसे संस्थान के पास इतना रुपया एकत्र होना कम आश्चर्यजनक नहीं है, जबकि जरुरतमंद मज़दूर स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में बेमौत मर रहे हैं। इसके लिये निगम का बड़ा ही मासूम सा तर्क है कि स्वास्थ्य सेवायें चलाने का अधिकार राज्यों की सरकारों का है।**

अपनी इस नाकामी को छिपाने के लिये ही निगम प्रति वर्ष सैंकड़ों करोड़ रुपये विज्ञापनबाजी पर खर्च करती है, जिसका उन मज़दूरों को कतई कोई लाभ नहीं जिनके वेतन से मोटा पैसा वसूला जाता है। इस तरह की तमाम फ़िज़ूलखर्चियों के बावजूद निगम के खजाने में 36000 करोड़ का मुनाफ़ा एकत्र हो चुका है। इतना ही नहीं इस में प्रतिवर्ष दो से चार हज़ार करोड़ की वृद्धि भी हो रही है। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाले ऐसे संस्थान के पास इतना रुपया एकत्र होना कम आश्चर्यजनक नहीं है, जबकि जरुरतमंद मज़दूर स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में बेमौत मर रहे हैं। इसके लिये निगम का बड़ा ही मासूम सा तर्क है कि स्वास्थ्य सेवायें चलाने का अधिकार राज्यों की सरकारों का है। इसलिये इनको चलाने का दायित्व उन्हें सौंपा गया है। इस पर होने वाले कुल खर्च का बजट, जाहिर है राज्य सरकारें ही बनाती हैं जिसका 88 प्रतिशत निगम वहन करता है।

शेष पेज 2 पर

'हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे'

- मनोज कुमार झा

घोटालों मे कीर्तिमान स्थापित कर चुकी सोनिया-मनमोहन सरकार का अब चला-चली की बेला में एक और बड़ा घोटाला प्रकाश में आ गया। यह सैन्य खरीद से जुड़ा हेलिकॉप्टर घोटाला है और सेनिया के मायके इटली से जुड़ा है। बोफोर्स घोटाला, जिसने मिस्टर क्लीन स्व. राजीव गांधी के चेहरे को दागदार बना दिया था, यद्यपि स्वीडन से जुड़ा था, पर उसका मुख्य दलाल क्वात्रोची इतालवी ही था। सोनिया से उसके घनिष्ठ संबंध जग जाहिर हैं। इस घोटाले की कई वर्षों तक जांच चली। राजीव गांधी को मरणोपरांत क्लीन चिट मिल गई और घोटालेबाजों का बाल तक बांका न हुआ। अब इस हेलिकॉप्टर घोटाले के प्रकाश में आने के बाद विदेश मंत्री जो स्वयं एक घोटालेबाज हैं

मौके की ताक में बैठे लुटेरे

(विक्लांगों का पैसा हड़प लिया) और रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी किया जायेगा, इटली की जिस कंपनी से हेलिकॉप्टर लिए गए, आगे उससे सौदा नहीं किया जायेगा, घोटाले की जांच होगी। पर सवाल है, अरबों का माल जो गड़प कर गए, क्या उन्हें सज़ा मिलेगी ? और सज़ा दो या न दो, माल बरामद होगा ? हर्गिज नहीं।

इधर इटली के प्रधानमंत्री रह चुके 'रंगीलेशाह' बर्लुस्कोनी कह रहें हैं कि इस तरह के सौदों में रिश्वत देना कोई अपराध नहीं, यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत परिपाटी है। गलत नहीं कह रहे हैं बर्लुस्कोनी। सौदों में दलाली ली-दी नहीं जाएगी तो बिज़नेस होगा ही नहीं। जितने भी बड़े अंतरराष्ट्रीय स्तर के सौदे होतें हैं, उनमें दलाली जरूरी है। सोचने की बात है, जब किसी मामूली सरकारी दफ़्तर की खरीदारी बिना कमीशन लिए नहीं हो सकती तो फ़िर अंतरराष्ट्रीय स्तर के रक्षा विभाग के इतने बड़े-बड़े सौदे भला बिना रिश्वत, कमीशन अथवा दलाली के कैसे हो सकते हैं ? इसलिये, सोनिया-मनमोहन सरकार को चाहिये कि एक अध्यादेश जारी कर सरकार द्वारा की जाने वाली किसी भी खरीद में रिश्वत लेना, एजेंटों द्वारा दलाली को कोई अच्छा-सा नाम देकर वैध घोषित कर दे। इससे घोटालों का झंझट ही सदा के लिये समाप्त हो जायेगा। आने वाली सरकारों को भी इससे बड़ी सहूलियत होगी। मीडिया को भी ऐसे सौदों पर शोर मचाने का कोई मौका नहीं मिलेगा। और यह चला चली की बेला है। जाते-जाते सोनिया-मनमोहन सरकार ऐसा कर दे तो भारतीय जनतंत्र के इतिहास में उसका नाम स्वर्णाक्षरों में अवश्य अंकित हो जायेगा।

बहरहाल, शासन में शुचिता तो न जाने कब की ही खत्म हो चुकी थी, सोनिया ने एक अच्छा काम यह किया कि जो झीना-सा परदा पड़ा रहता था सारे बुरे कामों पे, उसे तार-तार कर दिया और राजनीति को स्ट्रिप क्लब में तब्दील कर दिया। आखिर, बर्लुस्कोनी के देश की हैं सोनिया, जहां प्रधानमंत्री वेश्याओं का न्यूड डांस करवाता है, पैसे देकर 16-16 साल की लड़कियों के साथ सेक्स करता है और साफ कहता है कि रिश्वतखोरी गलत नहीं।

शेष पेज 2 पर